



2026:AHC:58886

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 9686 वर्ष 2026

दीपांशु यादव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : आशुतोष शुक्ला, शुभम यादव

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता(जी.ए.)

न्यायालय सं. - 67

माननीय अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति

1. श्री शुभम यादव, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री रोशन कुमार सिंह, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.) को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यह वर्तमान जमानत आवेदन अपराध संख्या 327 वर्ष 2025, बीएनएस की धाराओं 103(1), 238, 61(2), थाना पार्तापुर, जिला मेरठ में विचारण की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक प्रथम सूचनाकर्ता की पुत्री का देवर है और उसके विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। बल्कि, प्रथम सूचनाकर्ता ने दामाद के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाए हैं और आवेदक को उक्त दामाद का भाई होने के कारण झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त शंभू शरण यादव, जो प्रथम सूचनादाता की पुत्री के ससुर हैं, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. 1122 वर्ष 2026 में दिनांक 16.01.2026 को पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसलिए, आवेदक भी समान स्थिति में होने के कारण समता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, अतः अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और दिनांक 14.11.2025 से जेल में बंद है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.) ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया किंतु उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों पर विचार करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और अधिभारित जेलों तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए तथा **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **दीपांशु यादव** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो जमानतदारों के साथ व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को तथ्य बताने से हतोत्साहित करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।
 - ii. आवेदक कोई स्थगन मांगे बिना विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में लिप्त नहीं होगा।
 - iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
8. आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएँ।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित की गई हो कि 15 दिन के भीतर प्रमाणित प्रति दाखिल की जाएगी।
10. विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जमानत नीति रणनीति, संदर्भ में: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) सं. 4 वर्ष 2021, दिनांक 31.01.2023 के आदेश, (2024) 10 एससीसी 685 के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक को भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मार्च 23, 2026

एस.सी.

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।